CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
13
12 सितम्बर से 18 सितम्बर 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

गोद लेने की जटिल प्रक्रिया

सन्दर्भ

- 1 सितंबर से जिलाधिकारियों (डीएम) को अदालतों के बजाय गोद लेने के आदेश देने का अधिकार दिया गया है। अदालतों में लंबित सभी मामलों को अब स्थानांतरित किया जाएगा।
- देश में सैकड़ों दत्तक माता-पिता अब चिंतित हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया में और देरी होगी जो पहले से ही एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है।
- ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कार्यपालिका द्वारा पारित कोई आदेश तब पारित होगा जब एक दत्तक बच्चे के उत्तराधिकरो को अदालत के समक्ष चुनौती दी जाएगी।

संशोधित नियमों के बारे में

- किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम), 2015 में संशोधन करने के लिए संसद ने पिछले साल जुलाई में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया था।
- प्रमुख परिवर्तनों में जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को "कोर्ट" शब्द को हटाकर जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल था।
- एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार, यह "मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए" किया गया था।
- जिलाधिकारियों को अधिनियम के तहत बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करने का भी अधिकार दिया गया।
- अधिनियम और संबंधित नियम 1 सितंबर से लागू हुए। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 में संशोधन के अनुसार, "अदालत के समक्ष लंबित गोद लेने के मामलों से संबंधित सभी मामलों को इन नियमों के लागू होने की तारीख से जिलाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

क्या चिंता है ?

- संशोधित नियमों में माता-पिता, कार्यकर्ता, वकील और गोद लेने वाली एजेंसियां चिंतित हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से अदालतों में पहले से चल रहे मामलों को स्थानांतरित करना होगा और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा।
- गोद लेने के आदेश के लिए एक याचिका तब दायर की जाती है जब माता-पिता गोद लेने के लिए पंजीकरण करते हैं, जिसे बाद में एक गृह अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, एक बच्चे को संदर्भित किया जाता है और बाद में गोद लेने के आदेश तक बच्चे को पूर्व-गोद लेने वाले पालक देखभाल में ले जाने की अनुमति दी जाती है।
- इस तरह के आदेश में देरी का मतलब अक्सर यह हो सकता है कि एक बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकता है क्योंकि माता-पिता के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या जैसे यदि एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो माता-पिता स्वास्थ्य बीमा का दावा करने में असमर्थ होते हैं।
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का कहना है कि देश में विभिन्न अदालतों में गोद लेने के लगभग 1,000 मामले लंबित हैं।
- माता-पिता और वकील यह भी कहते हैं कि न तो न्यायाधीश और न ही डीएम को जेजे अधिनियम में बदलाव के बारे में पता है जिससे व्यवस्था में भ्रम और देरी हो रही है। कारा के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले एक पत्र का मसौदा तैयार कर रहा है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां गोद लेने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, या जल्द ही दिए जाएंगे, डीएम उन्हें वैध मानें। लेकिन इसको लेकर बड़ी चिंताएं भी हैं।
- "जिला मजिस्ट्रेट एक बच्चे को विरासत और उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान करने वाले नागरिक मामलों को नहीं संभालते हैं। अगर बच्चे के 18 साल के होने पर इन अधिकारों का विरोध किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायिक आदेश कहीं अधिक उचित है ताकि बच्चा अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया और संबंधित चुनौतियां

- भारत में दत्तक ग्रहण दो कानूनों - हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (HAMA) और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 द्वारा शासित होते हैं। दोनों कानूनों में दत्तक माता-पिता के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं।
- जेजे अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों को कारा के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है जिसके बाद एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद उम्मीदवार को गोद लेने के लिए योग्य पाया जाता है, गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित बच्चे को आवेदक को संदर्भित किया जाता है। HAMA के तहत, एक "दत्तक होम" समारोह या एक गोद लेने का विलेख या एक अदालत का आदेश अपरिवर्तनीय गोद लेने के अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन गोद लेने की निगरानी और बच्चों की सोर्सिंग की पुष्टि करने और यह निर्धारित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं कि माता-पिता गोद लेने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।
- कारा के तहत गोद लेने की प्रणाली में कई समस्याएं हैं लेकिन इसके मूल में यह तथ्य है कि इसकी रजिस्ट्री में बहुत कम बच्चे हैं।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गोद लेने वाले पूल में केवल 2,188 बच्चे हैं, जबकि 31,000 से अधिक माता-पिता बच्चे को गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कई लोगों को एक बच्चे को एक परिवार देने में सक्षम होने के लिए तीन साल तक इंतजार करने के लिए मजबूर करता है। इससे तस्कर HAMA में खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इन चिंताओं को अगस्त में एक संसदीय पैनल द्वारा "अभिभावकता और दत्तक ग्रहण कानून की समीक्षा" पर अपनी रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था, जिसने अनाथ और परित्यक्त बच्चों के जिला स्तर के सर्वेक्षण की सिफारिश की थी।
- नीलिमा मेहता के अनुसार, अन्य देशों की तरह "बाल-केंद्रित, वैकल्पिक, सक्षम और लिंग-न्यायिक" विशेष दत्तक-ग्रहण कानून की आवश्यकता है।
- "HAMA एक अभिभावक-केंद्रित कानून है जो उत्तराधिकारी, विरासत, परिवार के नाम की निरंतरता और अंतिम संस्कार के अधिकारों के लिए पुत्रहीन को पुत्र प्रदान करता है और बाद में बेटियों को गोद लेने को शामिल किया गया क्योंकि की परंपरा कन्यादान को हिंदू में धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
- जहां तक जेजे अधिनियम का संबंध है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ-साथ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मुद्दों को संभालता है और गोद लेने पर केवल एक छोटा भाग है।
- 2015 में, तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विभिन्न विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों, बच्चों की एक रजिस्ट्री, भावी दत्तक माता-पिता के साथ-साथ गोद लेने से पहले उनका मिलान करने के लिए CARA को सशक्त बनाकर संपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रणाली को केंद्रीकृत किया।
- इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और तस्करी को रोकना था क्योंकि बाल देखभाल संस्थान और गैर सरकारी संगठन कारा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बच्चों को सीधे गोद लेने के लिए दे सकते थे। लेकिन नई प्रणाली यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि परिवारों की जरूरत वाले अधिक बच्चों को इसके सुरक्षा जाल में लाया जाए।
- "कदाचारों की जांच करने और निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता थी। लेकिन नई व्यवस्था में गोद लेने का उद्देश्य ख़त्म हो गया था। मानवीय संपर्क, बंधन और मनोवैज्ञानिक तैयारी छीन ली गई है। इसलिए, माता-पिता बच्चे को गोद लेने के अन्य तरीकों पर विचार कर सकते हैं।" इसका एक और खतरनाक परिणाम यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, व्यवधान और विघटन की संख्या में वृद्धि हुई है, जहां बच्चों को गोद लेने की औपचारिकता के बाद वापस कर दिया जाता है।

कारा के बारे में:

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और अंतर-देश में गोद लेने की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है।
- 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण, 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- कारा मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने से संबंधित है।
- कारा को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अनुसार समय-समय पर गोद लेने से संबंधित मामलों पर नियम बनाने का भी अधिकार है।

भारत में बादल फटने का पूर्वानुमान अभी भी कठिन

- **बादल फटना** -छोटे से क्षेत्र में कम अवधि में अधिक और भारी मात्रा में बारिश होना - 19 वीं शताब्दी के मध्य से रिपोर्ट की गई है। फिर भी, इन घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान आसान नहीं हैं।
- हालांकि, उनके विनाशकारी प्रभाव जो जीवन और संपत्ति के नुकसान का कारण बनते हैं, बदलते माहौल में बढ़ रहे हैं और हाल के दशक में इन घटनाओं के बारे में समझ को आगे बढ़ाते हुए करीब से अवलोकन किया है।
- बादल किसी भी समय पृथ्वी की सतह का 70% भाग ढक सकते हैं, वे तैरते हुए महासागर की एक पतली परत की तरह हैं जिसमें लगभग एक इंच बारिश के साथ पृथ्वी की पूरी सतह को कवर करने के लिए पर्याप्त पानी है। एक मामूली आकार के बादल (1 घन किमी) में 5,00,000 लीटर से अधिक पानी हो सकता है। (सौ हाथियों के द्रव्यमान के बराबर।)
- बादल फटने की घटनाएँ अक्सर क्यूम्यलोनिम्बस बादलों से जुड़ी होती हैं जो गरज के साथ आती हैं और कभी-कभी मानसूनी हवा के झोंकों और अन्य मौसम की घटनाओं के कारण होती हैं। क्यूम्यलोनिम्बस बादल पूरे क्षोभमंडल (कभी-कभी 21 किमी तक) के माध्यम से 12-15 किमी की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और भारी मात्रा में पानी धारण कर सकते हैं।

विशेषताएं

- हालांकि, बादल फटने को बादल की विशेषताओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता है और यह बादलों के फटने का संकेत नहीं देता है। बादल फटने को वर्षा की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक घंटे में 100 मिमी बारिश को बादल फटना कहा जाता है। आमतौर पर बादल फटने की घटना 20 से 30 वर्ग किमी के छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होती है।
- भारत में, बादल फटना अक्सर मानसून के दौरान होता है, जब दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ अंतर्देशीय नमी की प्रचुर मात्रा में लाती हैं। भूमि पर अभिसरण करने वाली नम हवा पहाड़ियों से मिलते ही ऊपर उठ जाती है। नम हवा ऊंचाई तक पहुंच जाती है और संतृप्त हो जाती है तथा पानी हवा से संघनित होकर बादलों का निर्माण करने लगता है। इस तरह से बादल आमतौर पर बनते हैं, लेकिन एक मजबूत नमी अभिसरण के साथ इस तरह के भौगोलिक उत्थान के कारण तीव्र क्यूम्यलोनिम्बस बादल भारी मात्रा में नमी लेते हैं जो बादल फटने के दौरान पानी के रूप में धरती पर गिर जाते हैं।

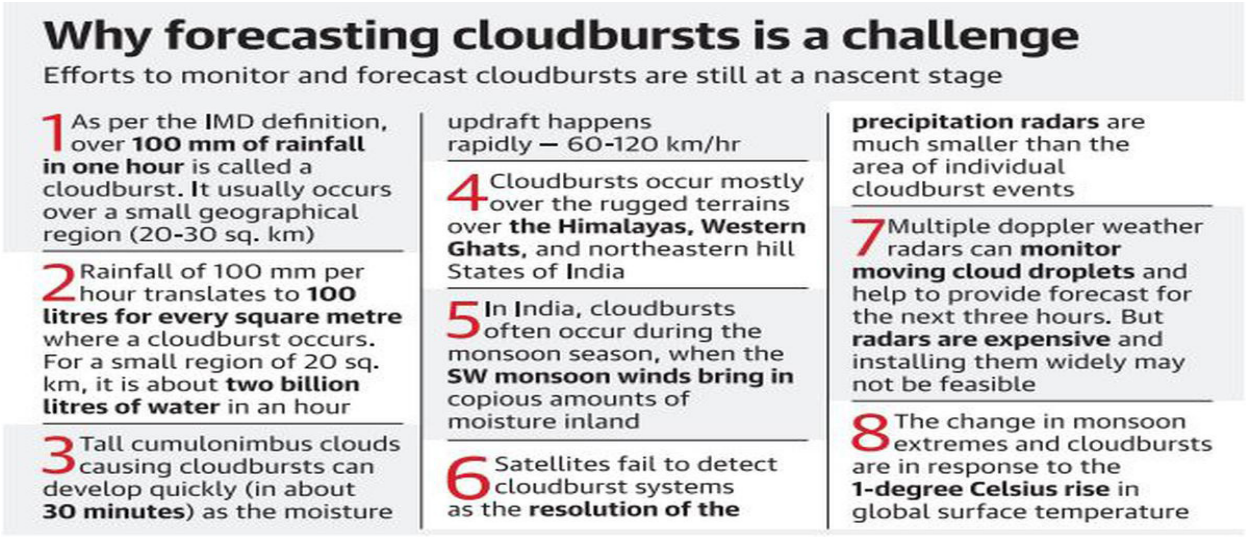

अधिक प्रवण क्षेत्र

- बादल फटना, इसलिए, ज्यादातर हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत के उत्तरपूर्वी पहाड़ी राज्यों के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में होता है। नाजुक खड़ी ढलानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मलबा बहता है, और अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश और लोगों का संपत्ति नुकसान होता है।
- हाल ही में बादल फटने से हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2003 में), लद्दाख (2010), और उत्तराखंड (2013) में हिमालय की तलहटी में महत्वपूर्ण तबाही हुई। वर्तमान मानसून मौसम (2022) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी घाट राज्यों से बादल फटने की सूचना मिली थी।

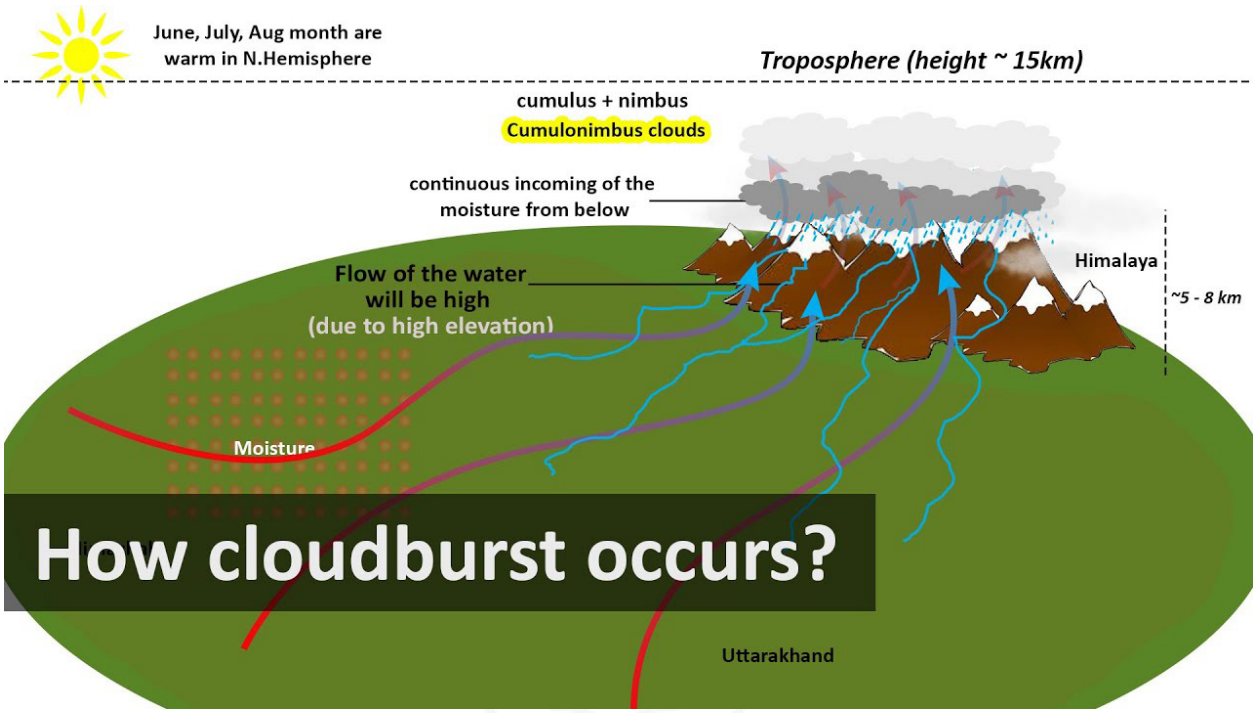

- 8 जुलाई, 2022 को, जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ मंदिर के रास्ते में लिद्दर घाटी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। हालांकि मीडिया ने इस घटना को मंदिर के ऊपर होने वाले बादल फटने से जोड़ा, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में इसे मान्य करने के लिए कोई मौसम संबंधी रिकॉर्ड नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान ने इस क्षेत्र के लिए छिटपुट हल्की बारिश का संकेत दिया, और आईएमडी ने मंदिर स्टेशन पर मध्यम वर्षा दर्ज की।

- जमीन पर निगरानी स्टेशन बदल फटने की अत्यधिक स्थानीय और कम होने के कारण मुश्किल से अनुमान किये जा सकते हैं। इसलिए, इन घटनाओं में से अधिकांश को क्षेत्र में निगरानी तंत्र की कमी के कारण रिपोर्ट नहीं किया जाता है, जिससे इन घटनाओं को पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है।

- सितंबर 2022 के पहले सप्ताह के दौरान भारी बारिश और जलभराव ने बेंगलुरू के जीवन की गति को लगभग रोक दिया। सोशल मीडिया पर अफवाह फ़ैल गई, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बादल फटने के दो साल पुराने वीडियो को बैंगलोर में बादल फटने के रूप में प्रसारित किया गया। शहर के किसी भी मौसम केंद्र ने बादल फटने की घटना दर्ज नहीं की, लेकिन सप्ताह के दौरान भारी बारिश का संकेत दिया क्योंकि अरब सागर में विकसित हो रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसूनी हवाओं ने ताकत हासिल कर ली।

- मुंबई (2005) और चेन्नई (2015) के मामले में, तट के साथ तेज मानसूनी हवाएं भी बादल फटने का परिणाम हो सकती थी। तटीय शहर विशेष रूप से बादल फटने की चपेट में था क्योंकि अचानक आने वाली बाढ़ इन शहरों में पारंपरिक तूफानी जल और बाढ़ प्रबंधन नीतियों को निष्क्रिय बना दिया था।

बादल फटने का पता लगाना

- जबकि उपग्रह बड़े पैमाने पर मानसून मौसम प्रणालियों का पता लगाने में बड़े पैमाने पर उपयोगी होते हैं, इन उपग्रहों के वर्षा राडार का संकल्प व्यक्तिगत बादल फटने की घटनाओं के क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा हो सकता है, और इसलिए वे अनिर्धारित हो जाते हैं। उच्च विभेदन पर बादलों का अनुकरण करने में मौसम पूर्वानुमान मॉडल को भी इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का कुशल पूर्वानुमान नमी अभिसरण और पहाड़ी इलाकों, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स और विभिन्न वायुमंडलीय स्तरों पर हीटिंग-कूलिंग तंत्र के बीच बातचीत में अनिश्चितताओं के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आईएमडी के पूर्वानुमान, सामान्य तौर पर, मौसम की भविष्यवाणी का परिदृश्य इस तरह आगे बढ़ा है कि व्यापक रूप से अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी दो-तीन दिन पहले की जा सकती है, लगभग एक सप्ताह पहले चक्रवात की भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि, बादल फटने का पूर्वानुमान अभी भी कठिन बना हुआ है।

- मल्टीपल डॉपलर वेदर राडार का उपयोग चलती बादलों की बूंदों की निगरानी के लिए किया जा सकता है और नाउकास्ट (अगले तीन घंटों के लिए पूर्वानुमान) प्रदान करने में मदद करता है। यह चेतावनियां प्रदान करने के लिए एक त्वरित उपाय हो सकता है, लेकिन रडार एक महंगा मामला है, और उन्हें पूरे देश में स्थापित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है।

- एक दीर्घकालिक उपाय स्वचालित वर्षा गेज का उपयोग करके बादल फटने की संभावना वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना होगा। यदि बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के साथ सह-स्थित हैं, तो इन स्थानों को खतरनाक के रूप में नामित किया जा सकता है। इन स्थानों पर जोखिम बहुत बड़ा होगा, और लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण और खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भूस्खलन और बाढ़ के प्रभाव बढ़ सकते हैं।

- जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि का अनुमान है। जैसे-जैसे हवा गर्म होती है, यह अधिक नमी और अधिक समय तक धारण कर सकती है। हम इसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन संबंध कहते हैं। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि नमी और वर्षा में 7-10% की वृद्धि के अनुरूप हो सकती है। वर्षा की मात्रा में यह वृद्धि पूरे मौसम में सामान्य रूप से नहीं फैलती है। जैसे-जैसे हवा की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक शुष्क अवधि रुक-रुक कर होती है और साथ ही अत्यधिक बारिश भी होती है। अधिक गहरे क्यूम्यलोनिम्बस बादल बनते हैं और बादल फटने की संभावना भी बढ़ जाती है।

बार-बार होने वाली घटनाएं

- देश भर से बादल फटने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। जलवायु परिवर्तन संकेत विशिष्ट है, लेकिन पास इसे प्रमाणित करने के लिए दीर्घकालिक (20 वर्ष या अधिक) प्रति घंटा डेटा नहीं है। आईएमडी अपने स्वचालित मौसम स्टेशनों को बढ़ाने के साथ, पास प्रति घंटा डेटा हो सकता है जो क्लाउडबर्स्ट-प्रवण क्षेत्रों को मैप करने में मदद कर सकता है।

- मानसून के चरम और बादल फटने में अब हम जो बदलाव देख रहे हैं, वह वैश्विक सतह के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के जवाब में है। जैसा कि उत्सर्जन में वृद्धि जारी है और उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता अपर्याप्त साबित होती है, ये तापमान 2020-2040 के दौरान 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2040-2060 के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना तय है। हमें जीवन और संपत्ति को चरम घटनाओं से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई और नीतियों की आवश्यकता होगी जो वैश्विक तापमान परिवर्तन के दोगुने होने पर बढ़ेगी।

अप्रत्याशित कर (WINDFALL TAX)

संदर्भ :

- रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, तेल और गैस कंपनियों पर एकमुश्त अप्रत्याशित कर के बारे में बाजारों में चर्चा हो रही है।

- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर केंद्र द्वारा लगाए गए अप्रत्याशित कर का बचाव करते हुए कहा कि यह एक तदर्थ कदम नहीं था बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद लिया गया था।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- विंडफॉल करों को एक बाहरी, कभी-कभी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है - उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य-वृद्धि।

- यह एक ऐसा लाभ हैं जिन्हें फर्म द्वारा सक्रिय रूप से किए गए किसी निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) एक अप्रत्याशित लाभ को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" के रूप में परिभाषित करता है।

- सरकारें आम तौर पर इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर एकमुश्त कर पूर्वव्यापी रूप से लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। एक क्षेत्र जहां इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है, वह है तेल बाजार, जहां कीमतों में उतार-चढ़ाव से उद्योग के लिए अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है।

- दुनिया भर में सरकारों के लिए अप्रत्याशित करों को लागू करने के लिए अलग-अलग तर्क हैं, जैसे- सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए, और सरकार के लिए एक पूरक राजस्व के रूप में।
- 1980 में, तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने देश के तेल उद्योग पर कच्चे तेल के अप्रत्याशित लाभ कर की शुरुआत की। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1979 और 1981 के बीच अमेरिकी सरकार ने तेल की कीमतों पर नियंत्रण जारी करना शुरू कर दिया था और अनुमान लगाया था कि इस विनियंत्रण से तेल कंपनियों को भारी मुनाफा होगा।
- इसका मतलब यह था कि सरकार द्वारा तब तक सीमित कीमतें विश्व बाजार के स्तर तक बढ़ जाएंगी और अमेरिकी सरकार की कराधान पर संयुक्त समिति ने अनुमान लगाया था कि विनियंत्रण से तेल उद्योग के मुनाफे में 400 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि होगी।
- विनियंत्रण के परिणामस्वरूप तेल उद्योग में जाने वाले राजस्व का अधिक हिस्सा वसूल करने के लिए, सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया।

जिन देशों ने इस तरह के कर लगाए हैं

- इटली और यूके दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया है।
- इटली का मामला- इटली ने ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर 25% कर लगाने की घोषणा की, ताकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक सहायता पैकेज में मदद की जा सके, जो ऊर्जा की बढ़ती लागत से मुश्किल से प्रभावित हुए हैं।
- यूके का मामला- यूके 26 मई, 2022 को या उसके बाद होने वाले मुनाफे पर टैक्स की हेडलाइन दर 40% से बढ़ाकर 65% कर देगा।
    - एक 'ऊर्जा लाभ लेवी' के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है और इसमें एक सनसेट क्लॉज़ भी शामिल होगा, जो 2025 के बाद कर को हटा देगा।

क्या है भारत का मामला?

- आसमान छूती महंगाई के बीच ईंधन, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर सार्वजनिक खर्च बढ़ रहा है।
- FY23 उर्वरक सब्सिडी बजट अनुमान 1.05 ट्रिलियन रुपये है।
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने मार्च तिमाही में बंपर मुनाफा और 2021-22 में रिकॉर्ड कमाई दर्ज की।

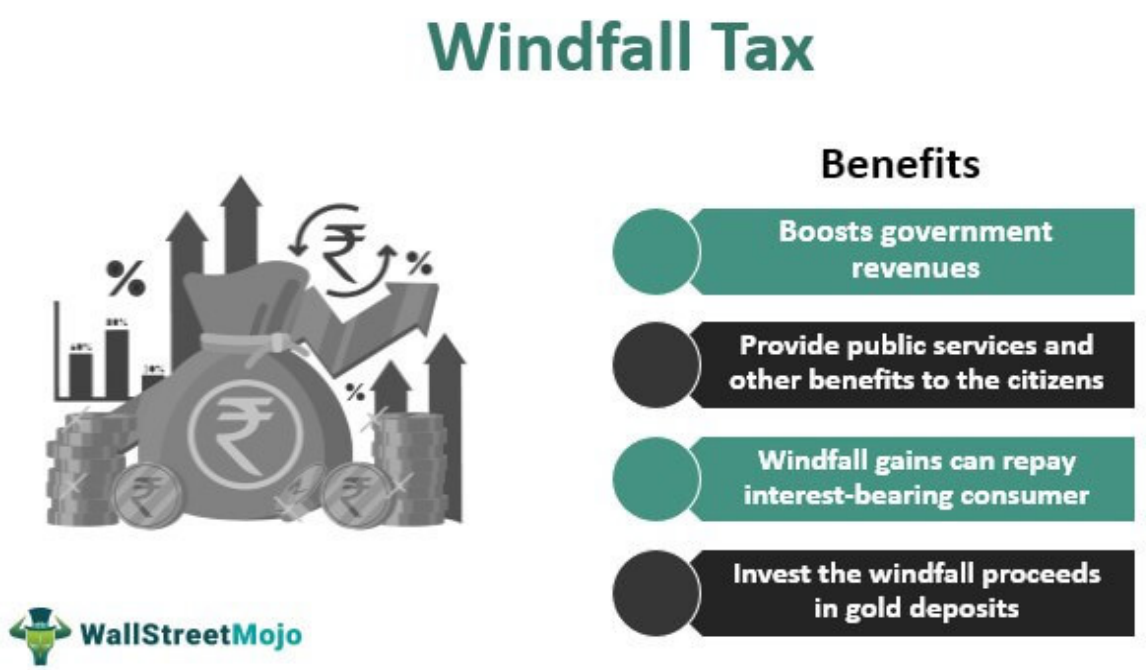

विंडफॉल टैक्स लगाने से पहले क्या अच्छी तरह विचार विमर्श करा जाना चाहिए?

- **मुनाफे से समझौता**
  1. अप्रत्याशित कर लगाने के लिए सरकार द्वारा पहला विचार उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) होगा।
  2. PSCs दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं जहाँ सरकार भी एक पार्टी होती है और जब कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार को भी लाभ होता है।
  3. इसलिए, सरकार को लाभांश और शेयर बायबैक पर समझौता करना पड़ता है, जिसका केंद्र लाभार्थी है।
- **रॉयल्टी:** दूसरा विचार रॉयल्टी और यथामूल्य शुल्क है।
- **निवेशक का विश्वास:** अगर कराधान नीति में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं, तो सरकार को इस पर विचार करना होगा कि एफडीआई नीति के तहत यह विदेशी निवेशकों को क्या संकेत देगा।
- **विंडफॉल टैक्स की आलोचना**
  - एकमुश्त कर, जिसे परिभाषा के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से लगाया जाता है, और मनमाना कर लगाया जाता है, जिसे भविष्य के करों के बारे में व्यवसायों में अनिश्चितता बढ़ जाती है।
  - विंडफॉल टैक्स लगाने को निवेश-विरोधी और व्यापार-विरोधी करार दिया गया है।

प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट

संदर्भ:

- एक मध्यम महामारी के पुनरुद्धार के बाद, भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत 16 महीने के निचले स्तर 150 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
- लेटेक्स की कीमत, जो दस्ताने निर्माताओं की भारी मांग के कारण महामारी के दौरान बढ़ गई थी, इसकी कीमतों में 120 रुपये से नीचे की गिरावट के साथ और अधिक गंभीर गिरावट आई है।
- गिरती कीमतों के प्रभाव से उनके दैनिक जीवन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा है, उत्पादकों ने गिरावट को रोकने में कथित देरी के लिए अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
- रबर उत्पादकों के लिए संगठन, रबर प्रोड्यूसर सोसाइटीज इंडिया के क्षेत्रीय संघों के राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में, पिछले सप्ताह केरल के कोट्टायम में रबर बोर्ड मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था।

कीमतों में तेज गिरावट की वजह

- कीमतों में मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से कमजोर चीनी मांग और यूरोपीय ऊर्जा संकट के साथ-साथ उच्च मुद्रास्फीति और आयात की अधिकता के साथ-साथ अन्य चीजे भी जिम्मेदार है।
- जबकि चीन में निरंतर शून्य Covid रणनीति, जो वैश्विक माल का लगभग 42% खपत करती है, उद्योग को महंगा पड़ा है, विश्लेषकों ने आयात में तेजी को भी हरी झंडी दिखाई है।
- उनके अनुसार, घरेलू टायर उद्योग, विशेष रूप से आइवरी कोस्ट से ब्लॉक रबर के रूप में और सुदूर पूर्व से मिश्रित रबर के रूप में पर्याप्त सूची पर है।

प्राकृतिक रबर के उत्पादन और खपत के मामले में भारत की स्थिति

- भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबर का दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यह विश्व स्तर पर सामग्री का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है। (भारत की कुल प्राकृतिक रबर खपत का लगभग 40% वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है)

- रबर बोर्ड की एक नवीनतम रिपोर्ट ने 2022-23 के दौरान भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन और खपत को क्रमशः 8,50,000 टन और 1,90,000 टन होने का अनुमान लगाया है। सामग्री का उत्पादन पिछले वर्ष के 7,15,000 टन की तुलना में 2021-22 के दौरान 8.4% बढ़कर 7,75,000 टन हो गया। वर्ष के दौरान उपज में वृद्धि, दोहन योग्य क्षेत्र और उपयोग किए गए क्षेत्र ने उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया।
- मांग पक्ष पर, घरेलू खपत 12.9% बढ़कर 2021-22 में 12,38,000 टन हो गई, जो पिछले वर्ष में 10,96,410 टन थी। प्राकृतिक रबर की खपत की कुल मात्रा का 73.1% ऑटो-टायर निर्माण क्षेत्र में होता है। इस बीच, सामग्री का आयात 4,10,478 टन से बढ़कर 5,46,369 टन हो गया।

गिरती कीमत उत्पादकों को कैसे प्रभावित करती है?

- टर्नअराउंड ने उत्पादकों को उजागर किया है - ज्यादातर छोटे और मध्यम पैमाने पर - एक प्रतिकूल गणना, केरल में व्यापक अफवाह प्रसार में फैला दिया,जो कुल उत्पादन का लगभग 75% है। कीमतों में तेज गिरावट के साथ-साथ उच्च लागत ने भी उन्हें अनिश्चित स्थिति में रख दिया है, जिससे कुछ को उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- कीमतों में गिरावट का असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह से रबर की खेती पर निर्भर हैं और उनके पास खर्चों में कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसने संबंधित स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती पैदा कर दी है, जो केरल में त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है।
- यदि कीमतों में बदलाव दूर की कौड़ी लगता है, तो यह प्रवृत्ति लंबे समय में एक फसल स्विच या यहां तक कि रबर होल्डिंग्स के विखंडन को भी ट्रिगर कर सकती है।

किसान की मांग

- उन्होंने केंद्र सरकार से जो प्रमुख मांगें उठाई हैं, उनमें लेटेक्स उत्पादों और मिश्रित रबर पर आयात शुल्क को बढ़ाकर प्राकृतिक रबर के बराबर करने के लिए 25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने की मांग की है।
- राज्य सरकार से इसकी मांग है कि केरल में फिर से रोपने की सब्सिडी 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत फसल का समर्थन मूल्य 170 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया जाए।

रबड़ बोर्ड

- सभी निराशाओं के बीच, रबड़ बोर्ड अपेक्षाकृत आशावादी होने का दावा करता है क्योंकि यह मूल्य में उतार-चढ़ाव को चक्रीय मानता है और मौजूदा वृक्षारोपण में पुराने पेड़ों के स्थान पर धीमी गति से प्रत्यारोपण के कारण अब से सात साल बाद रबड़ की उल्लेखनीय कमी के अनुमानों पर अपनी आशा रखता है। . कहा जाता है कि एजेंसी, कुछ समय के लिए कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कार्यक्रमों के एक सेट पर भी काम कर रही है।

संक्षेप में :

- महामारी के बाद के पुनरुद्धार के बाद, भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत 16 महीने के निचले स्तर 150 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। रबर प्रोड्यूसर सोसाइटीज इंडिया के क्षेत्रीय संघों के राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में, पिछले सप्ताह केरल के कोट्टायम में रबर बोर्ड मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था।
- कीमतों में मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से कमजोर चीनी मांग और यूरोपीय ऊर्जा संकट के साथ-साथ उच्च मुद्रास्फीति और आयात की अधिकता के साथ-साथ अन्य चीजे भी जिम्मेदार है।
- रबर बोर्ड अपेक्षाकृत आशावादी होने का दावा करता है क्योंकि वह कीमतों में उतार-चढ़ाव को चक्रीय मानता है और अब से सात साल बाद रबर की उल्लेखनीय कमी के अनुमानों पर अपनी आशा रखता है।

पूर्वी आर्थिक मंच और भारत का संतुलन अधिनियम

संदर्भ:

- रूस ने 5 से 8 सितंबर तक सातवें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) व्लादिवोस्तोक की मेजबानी की। चार दिवसीय मंच उद्यमियों के लिए रूस के सुदूर पूर्व (आरएफई) में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक मंच है।

पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में

- ईईएफ की स्थापना 2015 में आरएफई में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
- ईईएफ क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है।
- ईईएफ में हस्ताक्षरित समझौते 2017 में 217 से बढ़कर 2021 में 380 हो गए, जिनकी कीमत 3.6 ट्रिलियन रूबल है।
- 2022 तक, इस क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।
- समझौते बुनियादी ढांचे, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित हैं।

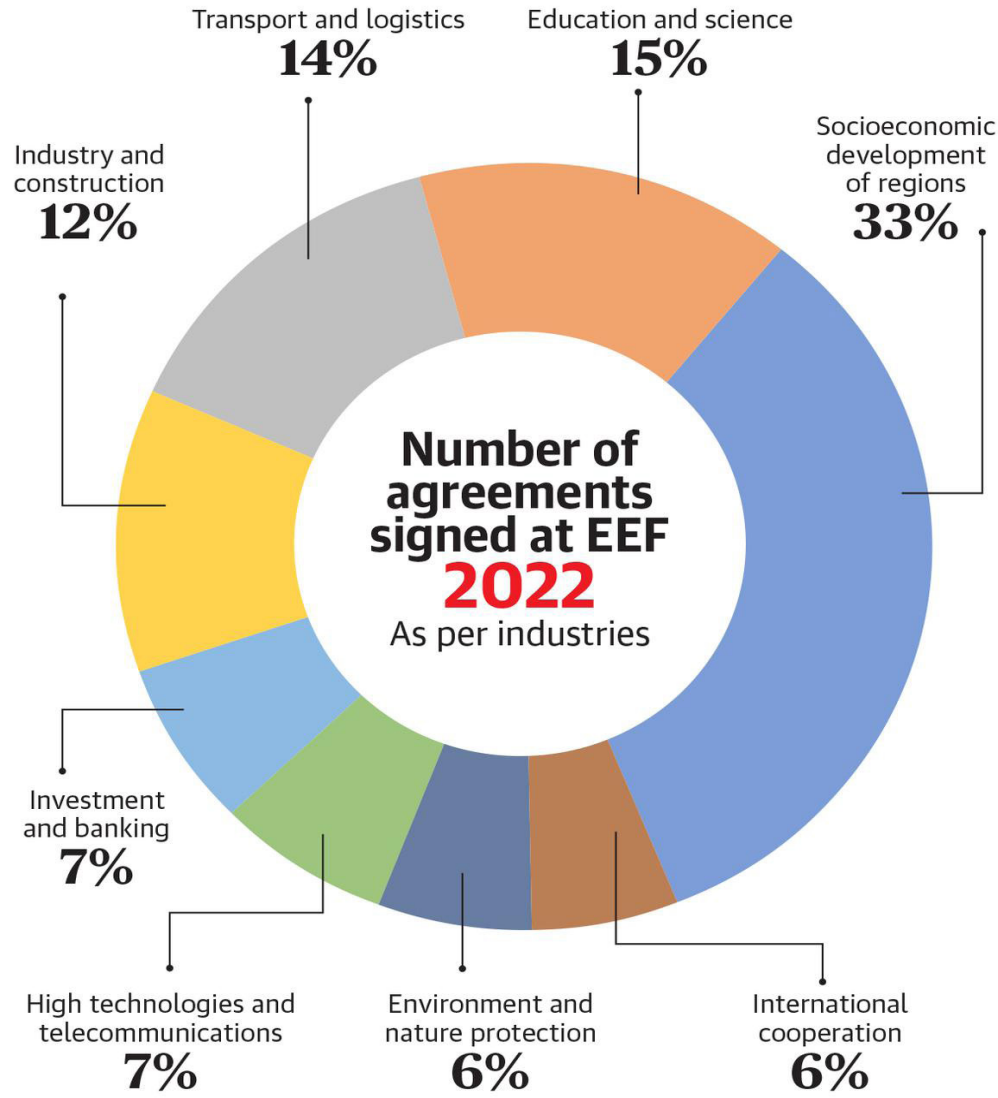

Source: Data from Eastern Economic Forum, forumvostok.ru

मंच के प्रमुख मेजबान और उनके हित

इस वर्ष फोरम का उद्देश्य सुदूर पूर्व को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ना है। चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेशक है क्योंकि उसे आरएफई में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पोलर सी रूट को बढ़ावा देने की क्षमता दिखाई देती है।

- इस क्षेत्र में चीन का निवेश कुल निवेश का 90% है। रूस 2015 से चीनी निवेश का स्वागत कर रहा है; यूक्रेन में युद्ध के कारण हुए आर्थिक दबावों के कारण अब पहले से अधिक स्वागत कर रहा है।
- ट्रांस-साइबेरियन रेलवे ने व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने में रूस और चीन की मदद की है। देश 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो उन्हें कुछ अवसंरचनात्मक सहायता के साथ एक-दूसरे के संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाता है। चीन अपने हेइलोंगजियांग प्रांत को भी विकसित करना चाहता है जो आरएफई से जुड़ता है।
- चीन और रूस ने 1,080 मीटर पुल के माध्यम से ब्लागोवेशचेंस्क और हेहे शहरों को जोड़ने, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने और निज़नेलिनिनस्कॉय और टोंगजियांग शहरों को जोड़ने वाले एक रेल पुल पर सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर चीन और आरएफई को विकसित करने के लिए एक फंड में निवेश किया है।
- चीन के अलावा, दक्षिण कोरिया भी इस क्षेत्र में अपने निवेश को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण परियोजनाओं, बिजली के उपकरणों के निर्माण, गैस-द्रवीकरण संयंत्रों, कृषि उत्पादन और मत्स्य पालन में निवेश किया है। 2017 में, कोरिया के निर्यात-आयात बैंक और सुदूर पूर्व विकास कोष ने तीन वर्षों की अवधि में RFE में $ 2 बिलियन का निवेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।
- सुदूर पूर्व में जापान एक अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। 2017 में, 21 परियोजनाओं के माध्यम से जापानी निवेश की राशि $16 बिलियन थी। शिंजो आबे के नेतृत्व में, जापान ने आर्थिक सहयोग के आठ क्षेत्रों की पहचान की और निजी व्यवसायों को RFE के विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
- जापान 2011 के फुकुशिमा में मंदी के बाद रूसी तेल और गैस संसाधनों पर निर्भर होना चाहता है जिसके कारण सरकार को परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलना पड़ा। जापान अपनी कृषि-प्रौद्योगिकियों के लिए एक बाजार भी देखता है जिसमें समान जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आरएफई में फलने-फूलने की क्षमता है।
- हालांकि, शिंजो आबे के साथ मौजूद व्यापार की गति योशीहिदे सुगा और फुमियो किशिदा के नेतृत्व के साथ खो गई थी। जापान और रूस के बीच व्यापार संबंध कुरील द्वीप विवाद से बाधित हैं क्योंकि दोनों देशों द्वारा उनका दावा किया जाता है।
- भारत RFE में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। मंच के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश के विस्तार में देश की तत्परता व्यक्त की।
- भारत ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, हीरा उद्योग और आर्कटिक में अपने सहयोग को बढ़ाने को इच्छुक है।
- 2019 में, भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $ 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी पेशकश की है। ईईएफ के माध्यम से, भारत का लक्ष्य रूस के साथ एक मजबूत अंतर-राज्यीय संपर्क स्थापित करना है। गुजरात और सखा गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधियों ने हीरा और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में समझौते शुरू किए हैं।

ईईएफ का उद्देश्य

- ईईएफ का प्राथमिक उद्देश्य आरएफई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में रूस का एक तिहाई क्षेत्र शामिल है और यह मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे और अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
- इस क्षेत्र में रहने वाली विरल आबादी लोगों को सुदूर पूर्व में स्थानांतरित करने और काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अन्य कारक है। क्षेत्र के धन और संसाधनों का रूस के सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत योगदान है। लेकिन सामग्री की प्रचुरता और उपलब्धता के बावजूद, कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण उनकी खरीद और आपूर्ति एक समस्या है।
- RFE को भौगोलिक रूप से एक रणनीतिक स्थान पर रखा गया है; जो एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। रूसी सरकार ने रूस को एशियाई व्यापारिक मार्गों से जोड़ने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से विकसित किया है।

- व्लादिवोस्तोक, खाबरोवस्क, उलान-उडे, चिता और अन्य शहरों के तेजी से आधुनिकीकरण के साथ, सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है।
- रूस सुदूर पूर्व के निवेश और विकास में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन युद्ध एक चिंताजनक मुद्दा है क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। हालांकि, रूस का मानना है कि वह चीन और अन्य एशियाई शक्तियों की मदद से आर्थिक संकट और प्रतिबंधों से बच सकता है।
- हालांकि, ईईएफ एक वार्षिक सभा है, फोरम रूस के लिए एक उपयुक्त समय पर आता है जो प्रतिबंधों के प्रभाव से निपट रहा है। इसके अलावा, म्यांमार, आर्मेनिया, रूस और चीन जैसे देशों का एक साथ आना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक प्रतिबंध-विरोधी समूह के गठन जैसा लगता है।

क्या भारत ईईएफ और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) के बीच संतुलन हासिल कर पाएगा?

- अमेरिका के नेतृत्व वाली समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) और ईईएफ इसके भौगोलिक कवरेज और मेजबान देशों के साथ साझेदारी के आधार पर अतुलनीय हैं।
- भारत के दोनों मंचों में निहित स्वार्थ हैं और उसने अपनी भागीदारी को संतुलित करने की दिशा में काम किया है। भारत मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद रूस द्वारा शुरू किए गए ईईएफ में निवेश करने से नहीं कतराता है।
- साथ ही, भारत ने IPEF में चार में से तीन स्तंभों को अपनी पुष्टि और स्वीकृति दे दी है। देश आरएफई में विकास में शामिल होने के लाभों को समझता है लेकिन यह आईपीईएफ को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी मानता है।
- आईपीईएफ चीन के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी या ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे अन्य क्षेत्रीय समूह का हिस्सा बने बिना, भारत के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने का एक आदर्श अवसर प्रस्तुत करता है।
- आईपीईएफ लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फोरम में भारत की भागीदारी चीन पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं से अलग होने में मदद करेगी और इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का हिस्सा भी बनाएगी।
- इसके अतिरिक्त, IPEF भागीदार कच्चे माल और अन्य आवश्यक उत्पादों के नए स्रोतों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कच्चे माल के लिए चीन पर भारत की निर्भरता और कम होगी। हालांकि, श्री मोदी ने आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ में पूर्ण भागीदारी से परहेज किया है, लेकिन यह मंच में भारत की भूमिका के अंत का संकेत नहीं देता है।

संक्षेप में

- पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना 2015 में रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। 2022 तक, इस क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।
- मंच के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश के विस्तार में देश की तत्परता व्यक्त की। भारत ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, हीरा उद्योग और आर्कटिक में अपने सहयोग को बढ़ाने को इच्छुक है।
- भारत का ईईएफ और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दोनों में निहित स्वार्थ है और उसने अपनी भागीदारी को संतुलित करने की दिशा में काम किया है। आईपीईएफ भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को अदालतों के बजाय गोद लेने के आदेश देने का अधिकार दिया गया है।
2. कारा को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अनुसार समय-समय पर गोद लेने से संबंधित मामलों पर नियम बनाने का भी अधिकार है।

सही कथन चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बादल फटने की घटनाएं अक्सर क्यूम्यलोनिम्बस बादलों से जुड़ी होती हैं।
2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक घंटे में 100 मिमी बारिश को बादल फटना कहा जाता है।

गलत कथन चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विंडफॉल टैक्स "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" है।
2. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर केंद्र द्वारा लगाए गए अप्रत्याशित कर का बचाव किया है

सही कथन चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबर का दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यह विश्व स्तर पर सामग्री का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है।
2. केरल, कुल रबर उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा उत्पादन करता है।

सही कथन चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. गलत कथन चुनें

(a) पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) की स्थापना 2015 में आरएफई में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

(b) ईईएफ पर हस्ताक्षर किए गए समझौते 2017 में 217 से बढ़कर 2021 में 380 हो गए, जिनकी कीमत 3.6 ट्रिलियन रूबल है।

(c) 2019 में, भारत ने रूस के सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $ 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी पेशकश की है।

(d) चीन इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है

उत्तर

1	2	3	4	5
C	D	C	B	D

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।